



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 1992/पौष 16, 1913
No. 6] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 1992/PAUSA 16, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1992

का.आ. 8(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित
प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त
धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों
की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे
प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना
दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से
जिसमें उस राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें उक्त अधिसूचना
अन्तर्दिष्ट है जनता को उपलब्ध करा दी जाती है सात
दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्-विचार किया जाएगा।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उपर्युक्त विनि-
दिष्ट अवधि की समाप्ति पर या उससे पहले उक्त प्रारूप
नियमों की बाबत किसी व्यक्ति में प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार
विचार करेगी। ऐसे आक्षेपों या सुझाव सचिव उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली-
11001 को भेजे जाने चाहिए।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम : इन नियमों का संक्षिप्त नाम ट्रेक्टर
उपकरण नियम, 1991 है।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जहाँ तक कि संदर्भ से
अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है।

(ख) "ट्रेक्टर" से अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्षक (10) के उपशीर्ष (1) के अधीन "कृषि मशीनरी" में आने वाला ट्रेक्टर अभिप्रेत है।

(ग) "उपकर" से अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन निकाली गई पूर्व भारी उद्योग विभाग की अधिसूचना सं. का. आ - 662 (अ) तारीख 6 सितम्बर, 1985 के निबंधनों के अनुसार उद्ग्रहीत उपकर अभिप्रेत है।

(घ) "कलक्टर" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर और जिसमें अपर कलक्टर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, उप कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सहायक कलक्टर उत्पाद-शुल्क और अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्मिलित हैं अभिप्रेत है।

(ङ) "विकास परिषद" से अधिनियम की धारा 6 के अधीन आटोमोबाइल और सहबद्ध उद्योगों के लिए लिए स्थापित विकास परिषद अभिप्रेत है।

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रस्तुत हैं ; और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित नहीं है अमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम या नियमों में है।

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का लागू होना—इन नियमों में, जैसा अन्यथा रूप से उपबंधित है, उसके सिवाए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसमें शुल्क के प्रतिदाय से संबंधित उपबंध भी हैं जहां तक हो सके, उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वे अधिनियम और नियमों के अधीन ट्रेक्टर के विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

4. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना—प्रत्येक विनिर्माता पूर्व मास के दौरान अपने उपक्रम में विनिर्मित या उत्पादित और वहां से हटाए गए ट्रेक्टर की मदों के समस्त सहायक की विवरणी इन नियमों के उपबंध में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक मास की 10 तारीख को या उससे पहले कलक्टर और विकास परिषद को प्रस्तुत करेगा।

2. यदि कोई विनिर्माता उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जिसे कलक्टर

या विकास परिषद के पास अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण विश्वास करने का कारण है तो कलक्टर विनिर्माता को उसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ट्रेक्टरों से संबंधित ममस्त या किसी भी लेखा को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा।

5. उपकर के आगम :- उपकर का आगम पहले शीर्ष 308 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वाणिज्य ट्रेक्टर पर उपकर के अधीन भारत की संचित निधि में जमा करा दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विधि द्वारा संसद द्वारा यथा विनियोग किए जाने के पश्चात् ऐसे आगम से संग्रहण लागत की कटौती करने के पश्चात् ऐसी राशि जो वह आवश्यक समझे विकास परिषद को सौंप देगी।

6. खाता खोलना . विकास परिषद द्वारा नियम 5 के अधीन प्राप्त की गई रकम भारतीय स्टेट बैंक में रखी जाएगी।

7. विकास परिषद के लेखे :- विकास परिषद नियम 5 के अधीन प्राप्त की गई रकम के संबंध में समुचित लेखे रखेगी।

2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखा विवरण लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

8. विकास परिषद का बजट प्राक्कलन :-

(1) विकास परिषद प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए ऐसी तारीख को या उससे पहले जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगी।

(2) कोई व्यय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट को स्वीकृति नहीं मिल जाती।

(3) बजट केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थ-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

9. विहित प्रशासनिक व्यय :-

विकास परिषद नियम 5 के अधीन अपने द्वारा प्राप्त रकम से ऐसी राशि का जो 2 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, कार्यालय स्थापन और उपस्कर लेखन सामग्री डाक महसूल, टेलीग्राम, टेलीफोन, टूलेक्स, सचिवालय में नियोजित कर्मचारियों की मजदूरी और भत्ते, सदस्यों के यात्रा और दैनिक भत्ते और परिषद का अधिवेशन करने से संबंधित व्ययों के लिए उपयोग कर सकेगी।

[फा. सं. 5/18/90-एईआई (III)]

ई. एन. मूर्ति, संयुक्त सचिव

उपाबंध

(नियम 4 देखें)

ट्रेक्टर उपकर नियम, 1991 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी का प्रारूप को
समाप्त होने वाला मास कारखाना का नाम
पता

उपकर के अध्यधीन माल का आरम्भिक अतिशेष		उपकर के अध्यधीन विनिर्मित माल		उपकर के अध्यधीन हटाए गए माल	
वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा
1	2	3	4	5	6
अन अतिशेष					
वर्णन	मात्रा	टिप्पण			
7	8	9			

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने / हमने उपरोक्त दर्शायी गई विनिर्णितियों का मेरे/हमारे कारखाने के अभिलेखों और बही से मिलान कर लिया है और जहाँ तक मैं/हम अभिनिश्चय करता हूँ/करते हैं वे यथार्थ और पूर्ण हैं।

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1992

S.O. 8(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published, as required by Sub-Section (1) of that section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification is made available to the public.

Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified will be considered by

the Central Government. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary, Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Tractor Cess Rules, 1991.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- 'Act' means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).
- 'Tractor' means tractor as covered under the Sub-heading (1) of Heading (10) 'Agricultural Machinery' of the First Schedule to the Act;
- 'Cess' means the cess levied and collected in terms of notification No. S O 662(E) dated 6th September, 1985 of late Department of Heavy Industry issued under Sub-section (1) of Section 9 of the Act;

(d) 'Collector' means the Collector of Central Excise and include the Additional Collector of Central Excise, the Deputy Collector of Central Excise, Assistant Collector of Central Excise and Superintendent of Central Excise;

(e) 'Development Council' means the Development Council for Automobiles and Allied Industries established under Section 6 of the Act;

(f) Words and expressions used herein and not defined in the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder, shall have the meaning respectively assigned to them in that Act or the rules.

3. Application of Central Excise and Salt Act and the rules made thereunder.—Save as otherwise provided in these rules, the provisions of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the rules made thereunder including those relating to refund of duty, shall, so far as may, apply in relation to the levy and collection of the cess as they apply in relation to the levy and collection of the duty of excise on manufacture of tractors under the Act and the rules.

4. Submission of returns.—(1) Every manufacturer shall submit to the Collector and to the Development Council on or before the 10th of every month a return in the Form specified in the Annexure to those rules of all stocks of items of tractors manufactured or produced in, and removed from his undertaking during the previous month.

(2) If any manufacturer fails to furnish the return within the date specified in sub-rule (1) or furnishes a return which the Collector or the Development Council has reason to believe is incorrect or defective, the Collector may serve notice on the manufacturer calling upon him to produce all or any of his accounts relating to the tractors manufactured or produced by him.

5. Proceeds of the cess.—The proceeds of the cess shall first be credited to the Consolidated Fund of India under the head "308—Union Excise duties—Cess on commodities tractors", and the Central Gov-

ernment may after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, hand over to the Development Council such sums as it may consider necessary from out of such proceeds after deducting therefrom the cost of collection.

6. Opening of Accounts.—The amount received by the Development Council under Rule 5 shall be kept in an account with the State Bank of India.

7. Accounts of the Development Council.—(1) The Development Council shall maintain proper accounts relating to the amount received by it under Rule 5.

(2) The audited statement of accounts for every financial year, together with the Auditor's Report thereon, shall be submitted to the Central Government.

8. Budget Estimates of the Development Council:—

(1) The Development Council shall in each year prepare a budget for the ensuing financial year and submit the same for sanction to the Central Government on or before such date as may be specified by the Central Government.

(2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government.

(3) The budget shall be prepared in accordance with such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

9. Prescribed administrative expenses.—The Development Council may utilise a sum, not exceeding 2 per cent of the amount received by it under Rule 5, to meet its expenses on account of office establishment and equipment, stationery postage, telegrams, telephones, telex, wages and allowances of staff employed in the Secretariat, travel and daily allowance of members and expenditure connected with holding of council meetings.

[File No. 5/18/90-AE1(III)]

E. N. MURTHY, Jt. Secy.

ANNEXURE

(See rule 4)

Form of Monthly Return to be submitted under the Tractor Cess Rules, 1991

Month Ending

Name of Factory

Address

Opening balance of goods subject to cess Goods subject to cess manufactured Goods subject to cess removed

Description	Quantity	Description	Quantity	Description	Quantity
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Closing Balance

Description	Quantity	Remarks
7.	8.	9.

I/We declare that I/we have compared the above shown particulars with the records and books of my/our factory and that they are in so far as I/we can ascertain, accurate and complete.

Signature of Manufacturer

